

VICTOR ACADEMY

भारत का केंद्रीय बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय वित्त मंत्री 'निर्मला सीतारमण' द्वारा 2019-20 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया गया।

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण' द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला बजट है।

केंद्रीय बजट:

किसी सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट अतीत में केंद्र के राजस्व और व्यय के बारे में विवरण देता है और आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्च और अनुमान।

'श्रीमती सीतारमण' के बजट भाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वर्ष में 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की राह पर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में और पिछले 5 वर्षों में 55 वर्षों से अधिक समय लगा।

सरकार ने 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ा है।

अब भारत पांच साल पहले 11 वें स्थान से ऊपर उठकर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

सरकार ने अपने कामों से दिखाया है कि "सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन" का सिद्धांत सफल हो सकता है।

सेक्टर-वार हाइलाइट्स

रोज़गार

ASPIRE के तहत, 2019-20 में स्थापित किए जाने वाले अस्सी लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमी।

भाषा कौशल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे विदेशों में नौकरी के अवसरों के लिए युवाओं द्वारा आवश्यक कौशल सेट पर ध्यान बढ़ाएं।

एक टीवी कार्यक्रम डीडी नेशनल पर शुरू होता है, विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप द्वारा स्वयं डिजाइन और निष्पादित किया जाता है।

बैंकों

केस के आधार पर किसी मामले में गैर-वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों में स्वामित्व हिस्सेदारी के 51% से कम स्तर पर जाने पर सरकार विचार कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को पूंजी को बढ़ावा देने और ऋण में सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।

PSB तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे एक PSB के ग्राहक को सभी PSB में भी सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2019-20 के दौरान वित्तीय रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs) की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि, पीएसबी को दी जाने वाली छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी।

NBFC के ऊपर RBI के नियामक प्राधिकरण को मजबूत करने के प्रस्ताव बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले आवास वित्त क्षेत्र पर विनियमन प्राधिकरण।

रेलवे

रेलवे इन्फ्रा को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी; पीपीपी का उपयोग यात्री माल सेवाओं के तेजी से विकास और वितरण को दिलाने के लिए किया जाता है।

विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) संरचनाओं जैसे रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के माध्यम से उपनगरीय रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे; रेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सार्वजनिक निजी भागीदार (पीपीपी) पहल।

2019 में लॉन्च होने वाला रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का एक विशाल कार्यक्रम।

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए पहले ही जीएसटी परिषद को स्थानांतरित कर दिया है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की आयकर कटौती प्रदान करेगी। FAME II योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है।

ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क।

कर

प्रत्यक्ष कर संग्रह में 78% की वृद्धि हुई; 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018 में 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया।

400 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली सभी कंपनियां अब 25% कॉर्पोरेट टैक्स दर के दायरे में रहेंगी।

यह सभी कंपनियों के 99.3% को कवर करेगा।

120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड है, इसलिए करदाताओं की आसानी के लिए।

मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव रखता हूं और जिनके पास पैन नहीं है, वे केवल आधार नंबर का हवाला देकर रिटर्न दाखिल करते हैं और जहां भी उन्हें पैन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग करते हैं।

किफायती आवास को और गति प्रदान करने के लिए, 45 लाख तक के घर की खरीद के लिए 31 मार्च 2020 तक उधार लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती।

इलेक्ट्रॉनिक मोड में फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट जिसमें कोई मानव इंटरफ़ेस शामिल नहीं है, इस साल चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा, ताकि करदाताओं के उत्पीड़न को कम किया जा सके।

जीएसटी

ताजा या वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2% ब्याज उपबंध के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन।

हम आगे #GST शासन को सरल बना रहे हैं"। एक सरलीकृत एकल मासिक रिटर्न को लुढ़काया जा रहा है, 5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।

पूरी तरह से स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल लागू किया जाएगा; एक के बाद एक होने वाले कई टैक्स लाईडर्स; एक केंद्रीय प्रणाली में कब्जा करने के लिए चालान विवरण।

कनेक्टिविटी

वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन

किया जाना है।

सरकार माल परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करती है, जो सड़कों और रेलवे को भी कम कर देगी।

देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है।

सरकार ने पीएमजीएसवाई, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास और यूडीएन योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की भौतिक कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर धक्का दिया है।

सीमा शुल्क

मेक इन इंडिया के पोषित लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाया जाना।

भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के आयात को मूल सीमा शुल्क से मुक्त नहीं किया जा रहा है।

घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयातित पुस्तकों पर 5% सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन

प्रत्येक गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव।

भारत 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो जाएगा। इस अवसर पर, राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।

गांधी-पिडिया

'गांधी-पीडिया' को भी विचार के गांधीवादी स्कूल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए विश्वकोश की तर्ज पर विकसित किया जाना है

शिक्षा और अनुसंधान

देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निधि के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना।

देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी; सभी मंत्रालयों के तहत उपलब्ध धन को एनआरएफ के साथ एकीकृत किया जाएगा।

भारतीय शैक्षिक प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति लाई जानी; उच्च में बड़े बदलाव के साथ ही स्कूल प्रणाली को पेश किया जाना है। 2019-20 में हेड, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के तहत

400 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना से अधिक। विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' शुरू किया जाना है।

डिजिटल भुगतान

नकद में व्यावसायिक भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए, बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लगाए जाने वाले 2% के स्रोत पर कर कटौती।

50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम लागत वाले डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं; इनके लिए ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई शुल्क या मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाएगा।

विनिवेश

चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी; एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू होगा; 2019-20 के लिए 1 लाख 5000 रुपये का विनिवेश लक्ष्य है।

ग्रामीण

2022 तक, कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होने वालों को छोड़कर हर एक ग्रामीण परिवार में बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी।

पीएमएवाई-ग्रामीण के दूसरे चरण में, पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले 1.95 करोड़ घर, 2019-20 से 2021-22 के दौरान; उनके पास एलपीजी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी।

अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

SFURTI ने 50,000 कारीगरों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 2019-20 में 100 नए समूहों को लागू किया।

पेंशन

प्रधान मंत्री करम योगी मानव धन योजना के तहत वार्षिक कारोबार वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये से कम किया गया।

अंतरिक्ष

व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को इसरो के लाभों का दोहन करने के लिए शामिल किया गया है।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज

इलेक्ट्रॉनिक धन उगाहने वाले मंच, एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक कल्याण उद्देश्यों के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों की सूची बनाने के लिए।

एनआरआई

भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड, भारत में उनके आगमन के बाद जारी किए जाने के लिए अनिवार्य 180 दिनों के लिए इंतजार किए बिना।

अनिवासी भारतीयों को भारतीय इक्विटी के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए, एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश मार्ग को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के साथ विलय किया जाना है।

बाहि-खाता

सीतारमण ने बजट दस्तावेजों को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की 'औपनिवेशिक' प्रथा से प्रस्थान किया और इसके बजाय एक चार गुना लाल-सूती कपड़े पर स्विच किया, जिसे 'बही-खाता' कहा जाता है।

यह 89 वां केंद्रीय बजट है, जो सरकार का वित्तीय विवरण है, जो अतीत में अपने राजस्व और व्यय का विवरण देने के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्च और अनुमानों का विवरण देता है।

टैक्स रेट	सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक (60से80साल)	अति वरिष्ठ नागरिक(80 से ऊपर)
0%	ढाई लाख रुपये तक	3 लाख रुपये तक	5 लाख रुपये तक
5%	2,50,001 से 5,00,000 तक	3,00,001 से 5,00,000 तक	शून्य
20%	5,00,001 से 10 लाख तक	5,00,001 से 10 लाख तक	5,00,001 से 10 लाख तक
30%	10 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक	10 लाख अधिक